

THINK IAS

JOIN SAMYAK

Samyak

An Institute For Civil Services

DAILY

CURRENT नामा

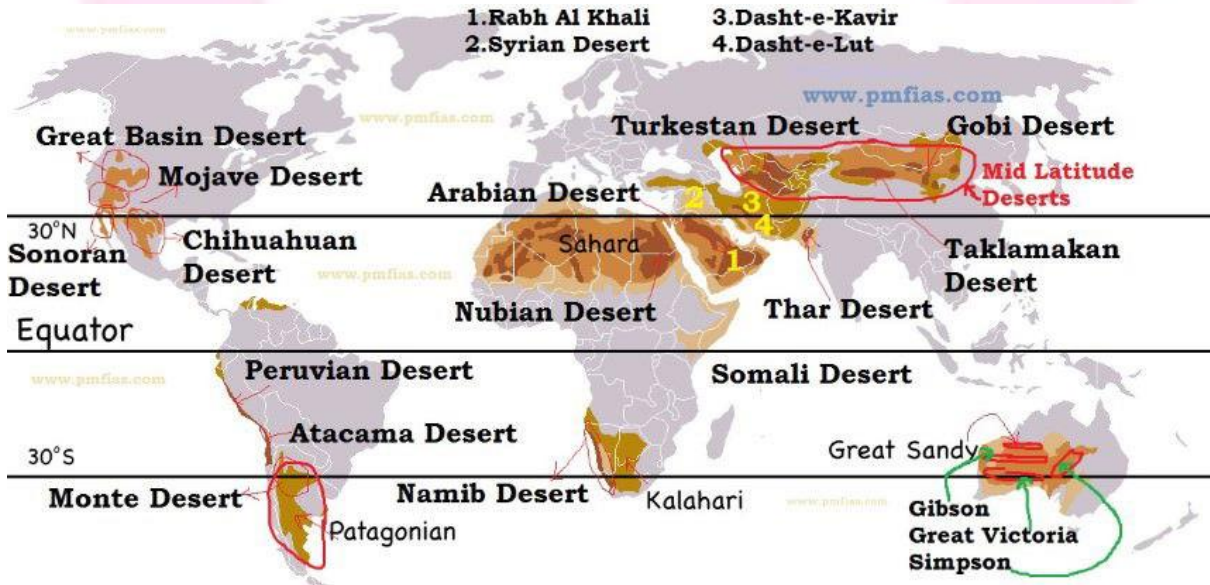
28 अगस्त

9875170111

SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

अटाकामा मरुस्थल

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-1: विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएँ



शिक्षा मंत्रालय ने 'साक्षरता', 'पूर्ण साक्षरता' को परिभाषित किया पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-1: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ

सुर्खियों में क्यों ?

- भारत में शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को संबोधित एक पत्र में 'साक्षरता' और 'पूर्ण साक्षरता' शब्दों को परिभाषित किया है, जो कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत वयस्क साक्षरता के लिए नए सिरे से किए गए प्रयास का हिस्सा है।
- शिक्षा मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक पूरे देश में 'पूर्ण साक्षरता' हासिल करना है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एक करोड़ शिक्षार्थियों को प्रति वर्ष शिक्षित करना है। यह कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल पर केंद्रित है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

- **उद्देश्य:** सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति वर्ष 15 वर्ष से अधिक आयु के एक करोड़ शिक्षार्थियों को शिक्षित करना।
- **इसके बारे में:** वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना।
- **घटक:**
 - बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता
 - महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, परिवार कल्याण, आदि।
 - प्रारंभिक (कक्षा 3-5), मध्य (कक्षा 6-8), और माध्यमिक चरण (कक्षा 9-12) समतुल्यता सहित बुनियादी शिक्षा।
 - स्थानीय रोजगार प्राप्त करने के लिए नव-साक्षरों के लिए कौशल विकास।
 - कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि में समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल होना।

साक्षरता और पूर्ण साक्षरता की परिभाषा:

- शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के साथ-साथ समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। 'पूर्ण साक्षरता' को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 95% साक्षरता प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे 100% साक्षरता के बराबर माना जाएगा।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रदर्शन:

- 2023 में, लगभग 4 मिलियन वयस्क शिक्षार्थी मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 3.6 मिलियन को साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया। 2024 में, उत्तीर्ण प्रतिशत घटकर 85.27% रह गया, जिसमें 3.4 मिलियन से अधिक लोग परीक्षा में शामिल हुए और लगभग 2.9 मिलियन को साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया।

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

महिलाओं के लिए लक्षित हस्तक्षेप: महिलाओं पर केंद्रित साक्षरता अभियान और समुदाय-आधारित कार्यक्रम लैंगिक अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय महिला संगठनों का उपयोग करके पहुँच को बढ़ाया जा सकता है।

बजट उपयोग में सुधार: निधि आवंटन और उपयोग के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करना संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

प्रांतीयता का समावेश: साक्षरता मूल्यांकन करने, सीखने के संसाधन प्रदान करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और टूल का उपयोग करने से अधिक शिक्षार्थियों तक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पहुँचने में मदद मिल सकती है।

स्थानीयकृत रणनीतियाँ: क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्रियों के उपयोग सहित स्थानीय संदर्भों के लिए साक्षरता कार्यक्रमों को अनुकूलित करना, शिक्षार्थियों के बीच भागीदारी और प्रतिधारण दर को बढ़ा सकता है।



अशिक्षितों की बड़ी संख्या: भारत के सामने एक बड़ी चुनाती है, क्योंकि 25.76 करोड़ वयस्क अशिक्षित हैं, जिनमें 9.08 करोड़ पुरुष और 16.68 करोड़ महिलाएँ शामिल हैं, जिससे 2030 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करना एक कठिन कार्य बन गया है।

लिंग असमानता: अशिक्षित महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी अधिक है, जो साक्षरता में लिंग अंतर को दर्शाता है, जिस पर लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

बजट उपयोग के मुद्दे: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि का उचित उपयोग ना होना कार्यक्रम कार्यान्वयन में अक्षमताओं का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, 2022-23 में ₹160 करोड़ में से केवल ₹76.41 करोड़ का उपयोग किया गया।

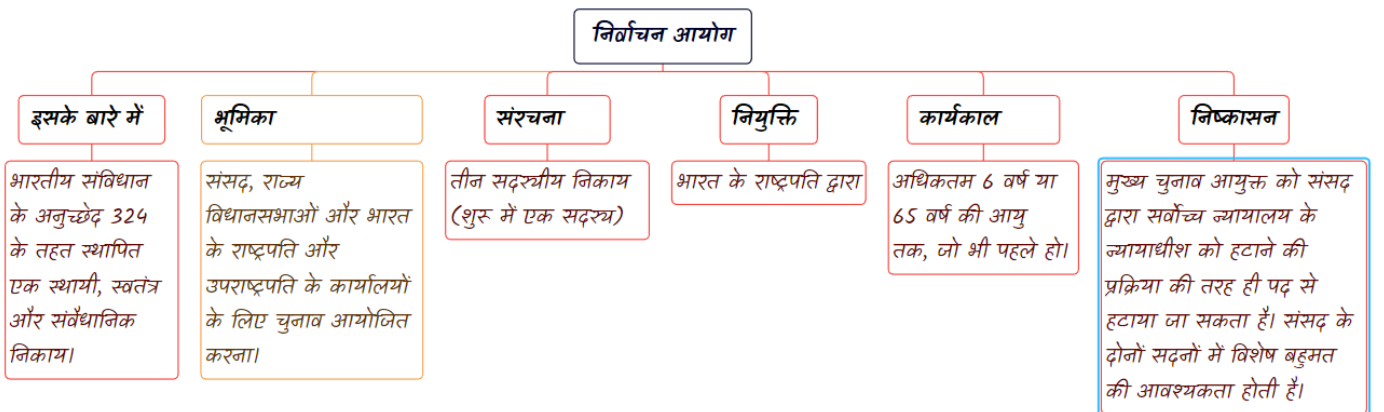
घटता हुआ पास प्रतिशत: FLNAT परीक्षाओं के लिए पास प्रतिशत में 2023 में 84% से 2024 में 85.27% तक की गिरावट साक्षरता कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में चुनातियों को उजागर करती है।

निर्वाचन आयोग

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-II: संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व।

सुर्खियों में क्यों ?

- भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की, जिससे पूरे भारत में पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि हुई।



संबंधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 324:** निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 325:** कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिये अयोग्य नहीं होगा।
- **अनुच्छेद 326:** लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
- **अनुच्छेद 327:** विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद 328:** किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिये निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 329:** निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक।

शक्ति और कार्य

- निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन
- सभी वैध मतदाताओं की अद्यतन सूची तैयार करना
- चुनाव की तारीखें और कार्यक्रम अधिसूचित करना
- चुनाव परिणाम घोषित करना
- चुनाव खर्च और आचार संहिता तय करना
- नामांकन पत्रों की जांच करना
- राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विवादों का निपटारा करना

ओपेक+ उत्पादन कटौती से भारतीय रिफाइनर अमेरिका से तेल खरीदने पर मजबूर हो सकते हैं
पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-III: विश्व आर्थिक संस्थाएँ

सुर्खियों में क्यों ?

- अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) ने बताया है कि भारत में तरल ईंधन की खपत 2028 तक उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 6.6 मिलियन बैरल प्रति दिन (एमबी/डी) हो जाने की उम्मीद है।
- इसके साथ ही, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देशों (ओपेक+) द्वारा उत्पादन में कटौती के कारण पश्चिम एशिया से कच्चे तेल के निर्यात में गिरावट आ रही है।
- इससे भारतीय रिफाइनर अमेरिका जैसे कच्चे तेल के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने के लिए बाध्य हो सकते हैं।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक)

- इसके बारे में - तेल निर्यातक देशों का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन।
- मिशन - अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना। अनावश्यक उतार-चढ़ाव को खत्म करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में तेल की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना।
- स्थापना - सितंबर 1960 में बगदाद, इराक में पांच देशों - ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा स्थापित।
- सदस्य - अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, नैजीर, लीबिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित 12 सदस्य।
- मुख्यालय - वियना, ऑस्ट्रिया।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों और सहयोगियों का संगठन (ओपेक+)

- **इसके बारे में:** तेल निर्यातक देशों का एक समूह जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है, यह तय करने के लिए नियमित रूप से मिलता है।

- **स्थापना:** 2016 में
- **उद्देश्य:** तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को समायोजित करने पर मिलकर काम करना।
- **योगदान:** यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लगभग 40% और प्रमाणित तेल भंडार के 80% से अधिक पर नियंत्रण रखता है।
- **सदस्य:** ओपेक देश के साथ अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, मलेशिया, दक्षिण सूडान, सूडान और ओमान।

मुद्रा 2.0 ऋणों का लक्ष्य अधिक समानता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना होना चाहिए

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-III: समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय

सुर्खियों में क्यों ?

- अपनी सफलता के बावजूद, मुद्रा 1.0 को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सबसे छोटे और सबसे हाशिए पर रहने वाले उद्यमियों तक पहुंचना था।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- **इसके बारे में:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में सरकार द्वारा एक प्रमुख पहल।
- **फोकस:** ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करके वंचित उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना।
- **उद्देश्य:** छोटे उधारकर्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
- **ऋण:** गैर-कृषि क्षेत्रों - विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवाओं के लिए ₹10 लाख तक।
- **पात्रता:** कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्र के लिए व्यवहार्य व्यवसाय योजना है और जिसके लिए ₹10 लाख से कम के ऋण की आवश्यकता है, वह आवेदन कर सकता है।
- **सब्सिडी:** इसके अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं है, लेकिन यदि कोई ऋण किसी सरकारी योजना से जुड़ा है जो पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, तो संबंधित लाभों के साथ इस योजना के तहत ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

ऋण की श्रेणियाँ:

शिशु ऋण

50,000/- रुपये तक। स्टार्ट-अप और पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता है।

किशोर

₹. 50,000 ₹. से 5 लाख तक मौजूदा व्यावसायिक इकाइयों के लिए जिन्हें स्थापना के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।

तरुण

₹. 5 लाख से ₹. 10 लाख तक मौजूदा स्थापित व्यावसायिक इकाइयों के लिए जिन्हें विस्तार के लिए धन की आवश्यकता है।

उत्तरी बाल्ड आइबिस विलुप्त होने के कगार से वापस लांटा

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-III: संरक्षण

सुर्खियों में क्यों ?

- उत्तरी बाल्ड(गंजा) आइबिस, जिसे बाल्ड्रैप के नाम से भी जाना जाता है, जो एक बार यूरोप में विलुप्त हो गया था, को प्रजनन और पुनर्वनीकरण प्रयासों के माध्यम से एक तरीके से पुनर्जीवित किया गया है। इस प्रजाति को अब "गंभीर रूप से लुप्तप्राय" के बजाय "लुप्तप्राय" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



उत्तरी बाल्ड(गंजा) आइबिस

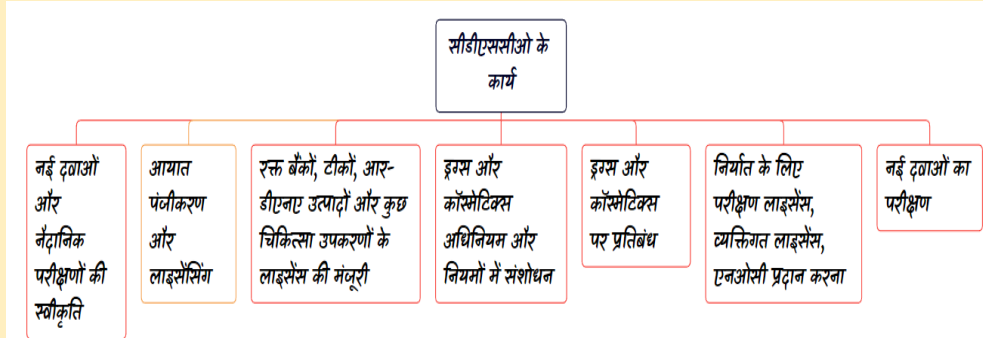
- इस पक्षी की चोंच लंबी एवं नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है। साथ ही यह इसके काले पंखों, इंद्रधनुषी हरे रंग और लाल सिर के कारण यह विशेष रूप से जाना जाता है।
- **आहार:** कीट लार्वा, केंचुए और अन्य अकशेरुकी
- **निवास:** छोटी घास वाले मैदान और चरागाह भूमि
- **जीवनशैली:** प्रजनन काल के दौरान साझेदारी वर्ष दर वर्ष बदलती रहती है।
- **प्रजनन:** जब घोंसले के निर्माण, ऊष्मायन और पालन-पोषण की बात आती है, तो यह जोड़ा एक टीम बन जाता है और ज़िम्मेदारियों को साझा करता है। वे चार हरे रंग के अंडे देते हैं।

अन्य खबरें

चर्चा का विषय	महत्वपूर्ण जानकारी
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन	<ul style="list-style-type: none"> • सुर्खियों में क्यों - केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सीमेंस हेल्थिनियर्स को एमपॉक्स का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण किट के निर्माण की मंजूरी दे दी है। किट का निर्माण कंपनी की वडोदरा स्थित आणविक निदान विनिर्माण इकाई द्वारा किया जाएगा। • मंकीपॉक्स <ul style="list-style-type: none"> • यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है (जानवरों से मनुष्यों में संक्रमण) • वायरस का प्राकृतिक होस्ट अभी भी अपरिभाषित है। लेकिन इस बीमारी के कई जानवरों में होने की सूचना मिली है। • यह पहली बार 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) के मनुष्यों में रिपोर्ट किया गया था • इससे फ्लू जैसे लक्षण और मवाद से भरी लूचा के घाव हो सकते हैं। • प्राथमिक संक्रमण संक्रमित जानवर के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या लूचा या म्यूकोसल घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। • मानव-से-मानव में संक्रमण निकट संपर्क के परिणामस्वरूप हो सकता है • मंकीपॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। अतीत में, एंटी-स्मॉलपॉक्स वैक्सीन को मंकीपॉक्स को रोकने में 85% प्रभावी दिखाया गया था।
	<p>केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन</p> <ul style="list-style-type: none"> • इसके बारे में: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत

चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए भारत का राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण ।

- **कार्य:** देश में चिकित्सा उपकरण के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण की देखरेख करना। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि चिकित्सा उपकरण सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता मानकों का अनुपालन करते हैं।
- **नोडल विभाग:** स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- **अध्यक्ष:** भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI)
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।



परिवेश पोर्टल 2.0

- **सुर्खियों में क्यों** - विदेशी जंगली प्रजातियाँ रखने वाले लोगों को संबंधित राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को परिवेश 2.0 पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन जमा करना आवश्यक है।
- **इसके बारे में:** पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र मंजूरी से संबंधित प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित एक वेब-आधारित वर्कफ्लो एप्लिकेशन।
- **विदेशी प्रजातियों से अर्थ:** वे जानवर या पौधे जिन्हें उनके प्राकृतिक आवास से किसी नए स्थान पर ले जाया जाता है।
- **मानदंड:** जीवित पशु प्रजातियाँ (रिपोर्टिंग और पंजीकरण) नियम, 2024 के अनुसार, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रजातियों को रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उनकी रिपोर्ट और पंजीकरण करना होगा।
- **वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022:** यह वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन परिशिष्टों और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध प्रजातियों के रखने, हस्तांतरण, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।

राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल

- **सुर्खियों में क्यों -** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल देश के सभी एलोपैथिक (एमबीबीएस) पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा।
- **इसके बारे में:** भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का एक पोर्टल। भारत में सभी एलोपैथिक (एमबीबीएस) पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक और गतिशील डेटाबेस, जो डॉक्टरों की आधार आईडी से जुड़ा होगा। यह व्यक्ति की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है।

निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) दवाएं

- **सुर्खियों में क्यों -** सरकार ने 156 निश्चित-खुराक संयोजन (एफडीसी) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें चेस्टन कोल्ड और फोरासेट जैसी लोकप्रिय दवाएं शामिल हैं, जिनका उपयोग क्रमशः सर्दी और बुखार और दर्द के लिए किया जाता है। यह प्रतिबंध निश्चित-खुराक संयोजन (एफडीसी) दवाओं पर सबसे व्यापक कार्रवाई है।
- **अर्थ:** एक ऐसा फार्मूलेशन जिसमें दो या अधिक सक्रिय औषधीय अवयव (API) एक ही खुराक के रूप में संयुक्त होते हैं, जैसे कि टैबलेट या कैप्सूल।
- **लक्ष्य समूह:** टीबी और मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए, जिनके लिए उन्हें नियमित रूप से कई दवाएँ लेने की जरूरत होती है।
- **लाभ:** रोगी को हर दिन लेने वाली गोलियों की संख्या कम हो सकती है और उपचार के पालन में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

चुर्नातियाँ

ऐसे संयोजन कई बार मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य या नैदानिक परीक्षणों पर आधारित नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह अतार्किक संयोजन दवा प्रतिरोध (विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं में) और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकते हैं।

भारत में इन संयोजनों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण कमियाँ हैं।

भारत में दवा उद्योग निश्चित खुराक संयोजनों के उत्पादन और विपणन में भारी निवेश करता है। इन निश्चित खुराक संयोजनों पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें सीमित करने के प्रयासों को निर्माताओं, व्यापार निकायों और यहाँ तक कि कुछ चिकित्सकों से भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।